सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाना

514. **डा० अबरार अहमद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाने (जयपुर उद्योग) का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को कब भेजा गया था;

(ख) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब लिया गया था तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारखाने को पुन: प्रारम्भ किये जाने की कोई संभावना है; यदि नहीं तो मजदूरों को पिछले चार वर्षों का बकाया वेतन किस प्रकार दिया जाएगा और कब दिया जायेगा;

(घ) क्या किसी उद्योग के बन्द होने के मामले में अथवा उसमें उत्पादन बन्द हो जाने के मामले में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड मजदूरों को देय बकाया वेतन का भुगतान करने के प्रश्न पर भी विचार करता है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सवाई माधोपुर में कोई उद्योग लगाने का विचार रखती है ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन): (क) से (घ) सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाने का मामला 1987 में बी०आई०एफ०आर० में भेजा गया था । बी.आई.एफ.आर. अपने तारीख 30 जनवरी, 1989 के आदेश में प्रथम-दृष्टि में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मै० जयपुर उद्योग लि० को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन जीव्य नहीं बनाया जा सकता और यह उपर्युक्त व न्यायोचित होगा कि इसे परिसमाप्त कर दिया जाए । एक प्रवर्तक द्वारा अपील प्राधिकरण, बी.आई.एफ.आर. में इस आदेश को चुनौती दी गई थी । इस बीच राजस्थान सरकार ने एक निजी कंपनी अर्थात् मै० गनोन हंकरली एंड कंपनी लि० को प्रतिष्ठित करके एकक के पुनरुज्जीवन के लिए बी.आई.एफ.आर. को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । बी.आई.एफ.आर. ने मामले पर विचार किया और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई.आर.बी.आई.) को एक पुन:स्थापना पैकेज तैयार करने का निदेश दिया । आई.आर.बी.आई. ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । पिछली सुनवाई 6-1-92 को हुई थी ।

पुनरुज्जीवन/पुन:स्थापना संबंधी प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ साथ कामगारों को वेतन की बकाया राशि का भुगतान शामिल है ।

(ङ) सरकार का सवाई माधोपुर में कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, नयी औद्योगिक नीति के तहत भावी उद्यमी स्थापना-स्थल व पर्यावरण संबंधी शर्तों को पूरा करके कोई भी उद्योग (अनिवार्य लाइसेंसीकरण के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर) लगाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

उद्योगों का कार्यकरण

515. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लगभग 155 उद्योगों के कार्यकरण के संबंध में एक अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त अध्ययन के अनुसार यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 1 अप्रैल से 13 दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान इन उद्योगों की विकास दर ऋणात्मक थी ;

(ग) यदि हां, तो उर्वरक, सीमेंट, आधारिक धातुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्योगों की उत्पादन

दर में पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान की उत्पादन-दर की तुलना में कितनी कमी आयी है ;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में इस उत्पादन-दर को बढ़ाने के लिए किसी नए उपाय पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां । उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग प्रत्येक माह 155 उद्योगों का अध्ययन करता है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई०आई०पी०) का 85.5 प्रतिशत भाग है । अप्रैल-नवम्बर, 1991 से संबंधित नवीनतम अध्ययन से यह पता चलता है कि 81 उद्योगों ने, जिनका आई आई पी में 61.3 प्रतिशत भाग है, सकारात्मक विकास दरें दर्शायी थी जबकि उन 74 उद्योगों का 24.2% भाग है । जिन्होंने सकारात्मक विकास दरें दर्शायी थीं ।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1990 में परिवर्तन दर की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 1991 के दौरान परिवर्तन दर का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

उद्योग	परिवर्तन की प्रतिशत दर	
	अप्रैल-नव. 1990	अप्रैल-नव. 1991
उर्वरक	17.3	3.1
सीमेंट	5.6	9.0
आधारभूत धातु	2.7	8.6
उपभोक्ता विकास वस्तुयें	17.1	(−)11.7

(घ) और (ङ) सरकार ने एक औद्योगिक नीति वक्तव्य प्रकाशित किया है जो 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा में रखा गया था । नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य नियन्त्रणों में ढील देकर और नौकरशाही विलंबों को दूर करके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है । सरकार द्वारा आयात प्रतिबंधों में ढील देकर कच्चा-माल आवश्यक संघटक, आदि उपलब्ध कराये जाने के उपाय किए जा रहे हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में कुछ घोषणायें पहले ही कर दी हैं । सरकार पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अवसंरचनात्मक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन सुधारने और बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने का भी प्रयास कर रही है ।

सरकारी क्षेत्र के अधीन औद्योगिक एकक

516. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1991 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के अधीन कुल कितने औद्योगिक एकक थे ;

(ख) 31 मार्च, 1991 तक इन उद्योगों में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया था और इनमें वर्ग-वार कितने-कितने कर्मचारी थे ।

(ग) उपर्युक्त निवेश राशि में से कितनी धनराशि ब्याज पर उधार ली गई थी और उस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों ने वर्ष 1990–91 के दौरान शुद्ध लाभ भी कमाया है; और

(ङ) यदि हां, तो शुद्ध लाभ की राशि कितनी थी ?